विभाग में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ तथा उनका अंग्रेजी/हिंदी में वाक्य प्रयोग

क्र.सं./S.No.	अंग्रेजी शब्द/Words in English	हिंदी में अर्थ/ Meaning in Hindi	अंग्रेजी में प्रयोग/Usages in English	हिंदी में प्रयोग/Usages in Hindi
1.	Cold storage capacity	शीत भांडागार क्षमता	As per a study on All India Cold-chain Infrastructure Capacity (AICIC-2015) conducted by NABCONS, it was reported that by 2014, there was cold storage capacity of 32 million tonnes in the country against an approximate requirement of 35 million tones.	नैबकॉन्स द्वारा कराए गए अखिल भारतीय शीत श्रृंखला अवसंरचना क्षमता (एआईसीआईसी- 2015) संबंधी अध्ययन के अनुसार यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2014 तक देश में लगभग 35 मिलियन टन की आवश्यकता की तुलना में 32 मिलियन टन शीत भांडागार क्षमता थी।
2.	Non-loanee farmer	गैर-ऋणी किसान	Due to the efforts made by the Government coverage of non-loanee farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has increased from 5% under erstwhile schemes to 34%.	सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण प्रधान मंत्री फसल बीमा के तहत गैर-ऋणी किसानों की कवरेज पूर्ववर्ती स्कीमों की तुलना में 5 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई है।
3.	Soil Health Card (SHC)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Government has been implementing 'Soil Health Card' (SHC) scheme since 2015 to assist State Governments in soil testing and providing soil health cards to all farm holdings in the country regularly in a cycle of 2 years.	राज्य सरकारों को मृदा परीक्षण करने तथा 2 वर्ष के चक्र में नियमित तौर पर देश के सभी भू-धारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में सहायता करने के लिए सरकार वर्ष 2015 से "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।
4.	Soil testing laboratories	मृदा परीक्षण	Under the Soil Health Management (SHM) scheme, Government is providing financial	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) स्कीम

		प्रयोगशालाएं	assistance to States for setting up / strengthening of various types of soil testing laboratories according to their requirement.	के अंतर्गत सरकार राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।
5.	Suicides among farmers	किसानों द्वारा आत्महत्या	The major causes of suicides among farmers are bankruptcy or indebtedness, farming related issues, family problems and illness, etc.	किसानों द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारण दिवालियापन अथवा ऋणग्रस्तता, खेती संबंधी मामले, पारिवारिक समस्याएं और बीमारी आदि हैं।
6.	Per Drop More Crop	प्रति बूंद अधिक फसल	Financial assistance @ 55% for small and marginal farmers and @ 45% for other farmers relating to the cost for installation of Drip and Sprinkler Irrigation systems is available under the Per Drop More Crop component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY-PDMC).	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत की दर से तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
7.	High Yielding Varieties	अधिक उपज वाली किस्में	The Government of India is providing financial assistance for production and distribution of improved/High Yielding Varieties (HYVs) seeds to the States and implementing agencies.	भारत सरकार राज्यों और कार्यान्वयक एजेंसियों को उन्नत/अधिक उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
8.	Seed Hub on Oilseeds	तिलहन बीज हब	One Seed Hub on Oilseeds has been established under the Rani Laxmi Bai Central Agricultural University, Jhansi which is	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अंतर्गत एक

			catering to the need of mustard seeds of Bundelkhand farmers.	तिलहन बीज हब स्थापित किया गया है जो बुंदेलखंड के किसानों की सरसों के बीजों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है।
9.	Net sown area	निवल बुवाई क्षेत्र	The net sown area in the country is 140130 thousand ha and net irrigated area is 68385 thousand ha.	देश में निवल बुवाई क्षेत्र 140130 हजार हेक्टेयर और निवल सिंचित क्षेत्र 68385 हजार हेक्टेयर है।
10.	Micro Irrigation	सूक्ष्म सिंचाई	Per Drop More Crop (PDMC) focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation technologies viz. Drip and Sprinkler Irrigation.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है।
11.	Minimum Support Price	न्यूनतम समर्थन मूल्य	Giving a major boost for the farmers income, the Government has approved the increase in the Minimum Support Price (MSPs) for all Kharif & Rabi crops for 2018-19 season at a level of at least 150 percent of the cost of production	किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
12.	Remunerative prices	लाभकारी मूल्य	PM-AASHA Scheme is aimed at ensuring remunerative prices to the farmers for their produce as announced in the Union Budget for 2018.	पीएम-आशा योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।
13.	Agro forestry	कृषि वानिकी	Under "Har Medh Par Ped", agro forestry is being promoted.	''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

14.	Integrated Nutrient Management	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन	Government of India has been promoting Integrated Nutrient Management (INM) i.e. soil test based balanced and judicious use of fertilizers (chemical, bio-fertilizers, organic manures like Farm Yard Manure, compost, vermi-compost, green manure etc) to maintain soil health and its productivity through Soil Health Card (SHC) scheme.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों (रासायनिक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों, जैविक खाद जैसे फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट, वर्मी- कम्पोस्ट, हरी खाद आदि) का मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है।
15.	Crop Cutting Experiment	फसल कटाई प्रयोग	As per provisions of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) admissible claims are generally paid by the insurance companies within two months of completion of Crop Cutting Experiments/harvesting period.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा आम तौर पर स्वीकार्य दावों का भुगतान फसल कटाई प्रयोगों/कटाई अवधि पूर्ण होने के 2 माह के भीतर किया जाता है।
16.	stress tolerant varieties	फसलों की दबाव सह्य किस्में	In order to meet the requirement of seeds during the natural calamities like flood and drought etc., the seed of small and medium duration, stress tolerant varieties of different crops reserved in National Seed Reserve (NSR) is distributed to farmers.	बाढ़ और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लघु एवं मध्यम अवधि के बीज, राष्ट्रीय बीज रिजर्व (एनएसआर) में आरक्षित विभिन्न फसलों की दबाव सह्य (स्ट्रेस टोलरेन्ट) किस्में किसानों को वितरित की जाती हैं।
17.	Farm based livelihood	कृषि आधारित आजीविका	Building market linkages through a value chain development approach for farm based livelihood is an important strategy being	कृषि आधारित आजीविका के लिए मूल्य श्रृंखला विकास दृष्टिकोण अपना कर मंडी

			pursued.	संपर्कों का विकास जैसी महत्वपूर्ण रणनीति अपनाने पर कार्य किया जा रहा है।
18.	Semi-arid climatic zone	अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र	New types of high yielding and less water requiring seed varieties that perform well under rain-fed conditions are provided to farmers for better production and productivity in semi-arid climatic zones for important kharif and rabi crops.	महत्वपूर्ण खरीफ और रबी फसलों के लिए अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए किसानों को अधिक उपज और कम पानी की आवश्यकता वाले नए किस्म के बीज उपलब्ध कराएं जाते हैं, जो वर्षासिंचित स्थितियों में भी अच्छी उपज देते हैं।
19.	Organic farming practices	जैविक खेती पद्धतियां	The Department has been focusing on creating awareness and educating the farmers about organic farming practices in the areas where clusters are formed.	यह विभाग उन क्षेत्रों जहां क्लस्टर का गठन किया गया है, में जैविक खेती पद्धतियों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने और शिक्षित करने पर फोकस कर रहा है।
20.	Drought	सूखा	The state of water scarcity/drought like situation depends upon the intensity and extent of South-West Monsoon, which varies from year to year.	पानी की कमी/सूखे जैसी स्थिति मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून की गहनता एवं अवधि पर निर्भर करती है जो हर वर्ष बदलती रहती है।
21.	Scheduled Desert Area	अनुसूचित मरूस्थल क्षेत्र	The Scheduled Desert Area which span across three States i.e. Rajasthan, Gujarat and Haryana is a summer breeding ground for the Locust.	अनुसूचित मरूस्थल क्षेत्र जो तीन राज्यों नामतः राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में फैला है, टिड्डियों के लिए एक ग्रीष्मकालीन प्रजनन क्षेत्र है।
22.	Income-centric approach	आय-केंद्रित दृष्टिकोण	The Government has been reorienting the agriculture sector by focusing on an income-centric approach as against the earlier	सरकार पहले की उत्पादन केंद्रित नीति से हटकर अब आय-केंद्रित दृष्टिकोण पर

			production centric policy.	ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र का पुनर्भिमुखीकरण कर रही है।
23.	online transparent competitive bidding system	ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली	National Agriculture Market (e-NAM) is envisaged as a pan-India electronic trading platform launched by Government of India on 14th April, 2016 with the objective of creating online transparent competitive bidding system to facilitate farmers with remunerative prices for their produce.	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की परिकल्पना भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को शुरू किए गए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली तैयार करना है।
24.	Value led enterprise	मूल्य आधारित उद्यम	The Committee on Doubling Farmers' Income (DFI) recognises agriculture as a value led enterprise.	किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति कृषि को एक मूल्य आधारित उद्यम मानती है।
25.	Pro-farmer initiative	किसान-समर्थक पहल	Giving a major boost to the pro-farmer initiatives, the Government has approved a new Umbrella Scheme 'Pradhan Mantri Annadata AaySanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)'.	किसान-समर्थक पहलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई प्रमुख (अम्ब्रेला) योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है।
26.	Registered pesticide	पंजीकृत कीटनाशक	Technical review of registered pesticides is being conducted from time to time for their continued use.	पंजीकृत कीटनाशकों के निरंतर उपयोग के लिए समय-समय पर उनकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है।
27.	Eligible farmers' family	पात्र किसान परिवार	The States/UTs were urged to expedite the process of enrolment of all eligible farmers' families under the PM-Kisan Scheme in a	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समयबद्ध तरीके से पीएम-किसान के तहत सभी पात्र

			time-bound manner.	किसान परिवारों के नामांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया था।
28.	Cultivable land	खेती योग्य भूमि	Ownership of cultivable land is the basis of the Scheme.	खेती योग्य भूमि का स्वामित्व इस योजना का आधार है।
29.	Pre and post–harvest crop losses	पूर्व एवं फसलोपरांत फसल हानियां	The Government of India has not conducted any specific study during the last three years to assess on pre and post–harvest crop losses.	भारत सरकार ने फसल पूर्व एवं फसलोपरांत फसल हानियों के आकलन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है।
30.	Agricultural implements	कृषि उपकरण	Agricultural implements and machinery are essential inputs for modern agriculture	कृषि उपकरण और मशीनरी आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक आदान हैं।
31.	Crop insurance	फसल बीमा	Crop insurance is a major risk mitigation tool for the benefit of farmers.	फसल बीमा किसानों के लाभ के लिए एक प्रमुख जोखिम शमन साधन है।
32.	in-situ crop residue management machinery	फसल अवशेष स्वस्थाने प्रबंधन मशीनरी	The financial assistance for establishment of Custom Hiring Centres of in-situ crop residue management machinery is @ 80% of the project cost.	फसल अवशेष स्वस्थाने प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हॉयरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु परियोजना लागत की 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।
33.	High productivity	उच्च उत्पादकता	This focuses on achieving high productivity, reduced cost of cultivation and remunerative price on the produce, with a view to earning higher profits for the farmers.	इसका उद्देश्य उच्च उत्पादकता हासिल करके, खेती लागत कम करके और उत्पाद पर लाभकारी मूल्य दिलाकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है।
34.	quantum loss of crops	फसलों की हानि की मात्रा	The quantum loss of crops destroyed by stray and wild animals are managed by concerned State/Union Territories.	आवारा और जंगली पशुओं द्वारा नुकसान की गई फसलों की हानि की मात्रा का आकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

35.	Registration of soil samples	मृदा नमूनों का पंजीकरण	Soil Health Card Portal has been developed for registration of soil samples, recording test results of soil samples and generation of Soil Health Card (SHC) along with fertilizer recommendations.	मृदा नमूनों के पंजीकरण, मृदा नमूनों के परीक्षण परिणामों की रिकॉर्डिंग और उर्वरक सिफारिशों के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल विकसित किया गया है।
36.	Coconut seedling	नारियल का पौधा	The Government is aware that coconut seedlings are being produced through some private coconut nurseries.	सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी नारियल नर्सरियों द्वारा नारियल के पौधों का उत्पादन किया जा रहा है।
37.	Procurement of food grains	खाद्यान्नों की खरीद	Per farmer limit has not been fixed for procurement of food grains at Minimum Support Price (MSP).	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए प्रति किसान सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
38.	Structural reforms in agriculture	कृषि में संरचनात्मक सुधार	The need for understanding structural reforms in agriculture including encouraging corporate investment was emphasized.	कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करने सहित कृषि में संरचनात्मक सुधारों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
39.	Hailstorm	ओलावृष्टि	Increase in risk coverage by inclusion of risks of cloud burst and natural fire under localized calamities and hailstorm under post-harvest losses.	स्थानीयकृत आपदाओं के तहत बादलों के फटने और प्राकृतिक आग लगने तथा फसलोपरांत नुकसानों के तहत ओलावृष्टि को शामिल करके जोखिम कवरेज में वृद्धि की जाएगी।
40.	Agricultural productivity	कृषि उत्पादकता	The Government is fully committed to promoting sufficient and huge amount of investment in the farm sector to boost agricultural productivity in the country.	सरकार देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में पर्याप्त एवं बड़ी मात्रा में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

41.	timely credit	समय पर ऋण	The access to timely credit or finance is a critical determinant of profitability of agriculture.	समय पर ऋण या वित्त की पहुंच कृषि की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।
42.	Traditional Water Bodies	पारंपरिक जल निकाय	It focuses on Source augmentation, distribution, ground water development, lift irrigation, diversion of water from water plenty to water scarce areas, repair, restoration, and renovation of traditional water bodies.	यह संसाधन वृद्धि, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराना, मरम्मत, जीर्णोद्धार और पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार पर केंद्रित है।
43.	Plant protection agent	पादप संरक्षक कारक	It is used for quick composting of organic waste, soil health improvement and as plant protection agent.	इसका उपयोग जैविक कचरे के त्वरित विघटन, मृदा स्वास्थ्य सुधार और पादप संरक्षक कारक के रूप में किया जाता है।
44.	cropping pattern	फसल कटाई पद्धति	The cropping pattern in India is highly skewed toward crops that are water intensive.	भारत में फसल कटाई पद्धति उन फसलों के लिए लाभदायक है जहां पानी की सघनता अधिक है।
45.	value addition	मूल्य संवर्धन	The Budget 2019-20 promote invest widely in agriculture infrastructure and support private entrepreneurship for value addition in farm sector.	बजट 2019-20 कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से निवेश को बढ़ावा देता है और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के लिए निजी उद्यमिता का समर्थन करता है।
46.	farmers' distress	किसानों का संकट	The study concluded that frequent crop failure due to vagaries of monsoon, absence of assured water resources and attack of pest and diseases are the most important causes of farmers' distress.	अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि मानसून की अनिश्चितताओं, सुनिश्चित जल संसाधन न होने और कीट के हमलों और बीमारियों के कारण बार-बार होने वाली फसल क्षति किसानों के संकट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हैं।

47.	The policy of agriculture sector	कृषि क्षेत्र की नीति	The policy of agriculture sector focuses on achieving higher productivity, reduced cost of cultivation and remunerative prices on the produce to ensure higher profits for the farmers.	कृषि क्षेत्र की नीति किसानों के लिए उच्च लाभ सुनिश्चित करने के लिए उच्च उत्पादकता, उपज की कम लागत और उपज पर लाभकारी मूल्य पर ध्यान केंद्रित करती है।
48.	assessment of crop yield/losses	फसल उपज/नुकसान का मूल्यांकन	It is the endeavour of the Government to lower the insurance unit for assessment of crop yield/losses with use of technology.	यह सरकार का प्रयास है कि वह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसल उपज/नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए बीमा इकाई को कम करे।
49.	Notified crop	अधिसूचित फसल	Under the crop insurance schemes, claims are paid to only those farmers who had insured their crops and paid premium under any of the notified crop insurance scheme in the area notified by the State Government.	फसल बीमा योजनाओं के तहत दावों का भुगतान केवल उन किसानों को किया गया है जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया था और प्रीमियम का भुगतान किया था।
50.	Floriculture	पुष्प कृषि	Floriculture or flower farming is the study of growing and marketing flowers and foliage plants.	पुष्प कृषि या फूलों की खेती पुष्प उगाने और पुष्प विपणन तथा पत्तेदार पौधों अध्ययन है।
51.	Excessive use of fertilizers	उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग	Excessive use of fertilizers may pollute the underground water which may be hazardous to all living beings including humans, animals, birds etc.	उर्वरकों के अंधाधुंध एवं असंतुलित प्रयोग से भू-जल प्रदूषित होता है जो मानवों, पशुओं, पक्षियों इत्यादि सहित

				सभी सजीवों के लिए खतरनाक हो सकता है।
52.	Gramin Agricultural Markets (GrAMs)	ग्रामीण कृषि मण्डियां (जीआरएएम)	As per Union Budget 2018-19, the Government had announced development and upgradation of existing 22,000 Gramin haats into Gramin Agricultural Markets (GrAMs).	केन्द्रीय बजट 2018-19 के अनुसार, सरकार ने मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मण्डियों (जीआरएएम) में विकसित एवं अपग्रेड करने की घोषणा की है।
53.	Modern agriculture	आधुनिक कृषि	Improved agricultural implements and machinery are essential inputs for modern agriculture which enhances productivity besides reducing human drudgery and cost of cultivation.	आधुनिक कृषि के लिए उन्नत कृषि उपकरण तथा मशीनरी आवश्यक इनपुट हैं जो मानवों के कठिन श्रम तथा कृषि की लागत कम करने के अलावा उत्पादकता में वृद्धि करता है।
54.	drought-affected State	सूखा प्रभावित राज्य	Currently, no proposal to enhance the compensation/financial assistance to drought-affected States is under consideration.	वर्तमान में, सूखा प्रभावित राज्यों को मुआवजा/ वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
55.	Nursery development and plantation in farm land	कृषि भूमि में नर्सरी विकास और वृक्षारोपण	There is a provision for financial assistance for nursery development and plantation in farm land which will help the farmer get additional income and make their farming system more climate resilient and adaptive.	कृषि भूमि में नर्सरी विकास और वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जो किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करेगा और उनकी खेती प्रणाली को अधिक जलवायु सह्य और अनुकूल बनाएगा।
56.	Short term crop loans	अल्पकालिक फसल ऋण	The Government of India (GoI) has been implementing the Interest Subvention Scheme (ISS) since 2006-07 under which short term crop loans upto Rs.3.00 lakh are	भारत सरकार (जीओआई) वर्ष 2006-07 से ब्याज छूट योजना (आईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके तहत 3

			made available to farmers at subvented interest rate of 7% per annum.	लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
57.	judicious use of chemical pesticides	रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग	Integrated Pest Management (IPM) seeks to promote cultural, mechanical, biological methods of pest control and recommends judicious use of chemical pesticides.	समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) कीट नियंत्रण की कल्चरल, यंत्रीकृत, जीव-वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की सिफारिश करता है।
58.	land reform	भूमि सुधार	The role of the Central Government in the field of land reforms is only of an advisory nature.	भूमि सुधारों के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होती है।
59.	water harvesting & conservation	जल संचयन व संरक्षण	The 'Manual for Drought Management, 2016' highlights the various drought mitigation programmes and measures in vogue, such as construction of water harvesting & conservation structures, use of water saving technology, afforestation etc	'सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016' में निर्माण, जल बचत प्रौद्योगिकी का उपयोग, वृक्षारोपण आदि जैसे प्रचलित विभिन्न सूखा शमन कार्यक्रम और जल संचयन व संरक्षण संरचनाओं के उपायों को उजागर किया है।
60.	deterioration of natural resources	प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास	due to imbalanced use of fertilizers coupled with decreased in use of organic manure and over exploitation of ground water, there is deterioration of natural resources.	जैविक खादों के उपयोग में कमी तथा भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन के साथ-साथ उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है।
61.	increase in the cropping intensity	फसल गहनता में वृद्धि	its Report to the Government in September, 2018. The Committee on Doubling Farmers' Income (DFI) recognises agriculture as a value led enterprise and has identified seven major sources of growth, viz., improvement in crop productivity; improvement in livestock	किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित समिति' (डीएफआई) ने कृषि को एक मूल्य नीत उद्यम के रूप में पाया है और इसके विकास के सात मुख्य स्रोतों की

			productivity; resource use efficiency or savings in the cost of production; increase in the cropping intensity; diversification towards high value crops; improvement in real prices received by farmers; and shift from farm to non-farm occupations.	पहचान की है जैसे फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग में दक्षता या उत्पादन की लागत में कमी; फसल गहनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रूख; किसानों द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक मूल्य में सुधार; और कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में शिफ्ट।
62.	old age pension	वृद्धावस्था पेंशन	With a view to provide social security net for Small and Marginal Farmers (SMF) as they have minimal or no savings to provide for old age and to support them in the event of consequent loss of livelihood, the Government has decided to implement another new Central Sector Scheme for providing old age pension to these farmers.	वृद्धावस्था में आजीविका के साधन समाप्त होने और नाममात्र अथवा कोई भी बचत न होने पर छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को समाजिक सुरक्षा दिए जाने के प्रयोजनार्थ सरकान ने ऐसे किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए एक अन्य नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।
63.	restoring soil fertility	मृदा की उर्वरता को बनाए रखना	Ministry of Agriculture, Government of India is implementing National Food Security Mission (NFSM) in identified districts of all the 29 States of the country to increase the production and productivity of foodgrains through area expansion and productivity enhancement in a sustainable manner, thereby restoring soil fertility and productivity at the individual farm level.	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार देश के सभी 29 राज्यों के अभिज्ञात जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि स्थायी तरीके से क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहेगी और व्यक्तिगत कृषि स्तर पर उत्पादकता बढ़ेगी।

64.	Production of quality seed	गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन	In order to promote production of quality seed, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is always promoting production of quality seed and time to time appropriate amendments have been made in New Policy on Seed Development, 1988 and National Seed Policy, 2002.	गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय सदैव गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देता रहा है तथा उसने बीज विकास की नई नीति, 1988 एवं राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में समय-समय पर उचित संशोधन किए हैं।
65.	tenant farmer	काश्तकार	There is no evidence to suggest that tenant farmers have to continue farming as they do not have the knowledge/skill of any other work.	ऐसा कोई सुझाव देने का प्रमाण नही हैं कि किसी अन्य कार्य का ज्ञान/कौशल न होने के कारण काश्तकारों को कृषि जारी रखनी पड़ेगी।
66.	Crops diversification	फसल विविधीकरण	Crops diversification is intended to promote technological innovations for sustainable agriculture and enable farmers to choose alternative crops.	फसल विविधीकरण का आशय सतत कृषि के लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना तथा किसानों को वैकल्पिक फसलें चुनने के लिए समर्थ बनाना है।
67.	alternative crop	वैकल्पिक फसल	Meager reduction in production of paddy resulting from its replacement with alternative crops like pulses, oilseeds, coarse cereals, nutri cereals, cotton and agro forestry would not affect the overall foodgrain production due to increase in production of alternative crops.	धान के उत्पादन में अल्प कमी के परिणास्वरूप वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास एवं कृषि वानिकी के प्रतिस्थापन से वैकल्पिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण समग्र खाद्यान्न उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।
68.	appropriate dosage of nutrients	पोषक तत्वों की उचित	Soil health card provides information to the farmers on nutrient status of their soil along with recommendations on appropriate dosage	मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के तहत फसल उत्पादकता और मृदा उर्वकता में सुधार

		मात्रा	of nutrients to be applied for improving crop productivity and soil fertility.	लाने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा में सिफारिशों के साथ किसानों के खेतों की पोषक स्थिति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाती है।
69.	Bio-fertilizer	जैव उर्वरक	In view of the priority for the promotion of organic farming and reduction of chemical residues in the environment, special focus has to be given for the production of bio-fertilizers.	जैविक कृषि को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण में रासायनिक अपशिष्टों को कम करने की दृष्टि से जैव उर्वरकों के उत्पादन पर विशेष जोर देना होगा।
70.	The Community seed bank	सामुदायिक बीज बैंक	The Community Seed Banks (CSBs) are community seed banks are collections of seeds of local landraces that are maintained and administered by the communities themselves, Seeds can be stored by a community either in large quantity to ensure that planting material is available, or in small samples to ensure that genetic material is available even if varieties become endangered or extinct.	सामुदायिक बीज बैंक ऐसे बीज बैंक है जो स्थानीय किस्मों के बीजों का संग्रह करते हैं जिनका रखरखाव स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है। बीज को एक समुदाय द्वारा बड़ी मात्रा में संग्रहीत किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोपण सामग्री उपलब्ध है या छोटे नमूनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध है भले ही किस्में लुप्तप्राय या विलुप्त हो जाएं।
71.	Oilseeds	तिलहन	States have the option to roll out Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS) on pilot basis in district / selected APMC(s) of district involving the participation of private stockist for oilseeds.	राज्यों के पास तिलहन के लिए निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी वाले जिले के चुने हुए जिला / चयनित एपीएमसी (एस) में

				पायलट आधार पर निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को रोल आउट करने का विकल्प है।
72.	Improved market linkage	उन्नत मंडी संपर्क	Committee recognizes agriculture as a value led enterprise and suggests empowering farmers with “improved market linkages” and enabling “self-sustainable models” as the basis for continued productivity-production and income growth for farmers.	समिति कृषि को मूल्यवाहित उद्यम मानती है और उन्नत मंडी संपर्कों के साथ किसानों को सशक्त करने का सुझाव देती है तथा लगातार उत्पादकता-उत्पादन और किसानों के लिए आय वृद्धि के लिए आधार के रुप में ‘स्वंय सशक्त मॉडल’ को सक्षम बनाती है।
73.	strains	किस्म	Indian Council of Agricultural Research under Network Project on Soil Biodiversity – Biofertilizer has developed improved and efficient strains of biofertilizers specific to different crops and soil types	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा जैव विविधिता-जैव उर्वरक पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत विभिन्न फसलों तथा मृदा प्रकारों के उन्नत एवं सक्षम विशिष्ट जैव उर्वरकों की किस्मों को विकसित किया है।
74.	Real time information	सही समय पर जानकारी	The NCIP dashboard provides for State wise access of real time data for all seasons which includes real time information like total farmers enrolled, number of applications, sum insured, area insured, gender and category wise data, total premium etc.	एनसीआईपी डैशबोर्ड सभी मौसमों के लिए वास्तविक समय के डेटा की राज्यवार पहुंच प्रदान करता है जिसमें वास्तविक समय की जानकारी शामिल है जैसे कुल नामांकित किसान, आवेदनों की संख्या, बीमित राशि, बीमित क्षेत्रफल, लिंग और श्रेणी वार डेटा, कुल प्रीमियम आदि।
75.	Soil sample	मृदा नमूना	Soil Health Card Portal has been developed	मृदा नमूनों के पंजीकरण, मृदा नमूनों के

			for registration of soil samples, recording test results of soil samples and generation of Soil Health Card (SHC) along with fertilizer recommendations.	परीक्षण परिणामों की रिकॉर्डिंग और उर्वरक सिफारिशों के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल विकसित किया गया है।
76.	Localized risk	स्थानिकृत जोखिम	However, losses due to localized risks of hailstorm, landslide, inundation, cloud burst & natural fire and post-harvest losses are calculated on individual insured farm level by the joint committee of State Government and concerned insurance companies.	तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग लगने तथा फसलोपरान्त हानियों के स्थानिकृत जोखिमों के कारण होने वाली हानियों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कम्पनियों की संयुक्त समिति द्वारा एकल रूप में बीमित खेत के स्तर पर किया जाता है।
77.	Practices	पद्धतियां	The project seeks to mainstream biodiversity, climate change and sustainable land management objectives and practices into Indian agriculture.	इस परियोजना में जैव विविधता,जलवायु परिवर्तन और सतत भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और पद्धतियों को भारतीय कृषि की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है।
78.	Global environmental benefit	वैश्विक पर्यावरणीय लाभ	The overall objective of the project is to catalyze transformative change of India's agricultural sector to support achievement of national and global environmental benefits and conservation of critical biodiversity and forest landscapes.	इस परियोजना का समग्र उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन लैंडस्केपों के संरक्षण को सहायता देने के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करना है।
79.	Nursery raising	पौधशाला निर्माण	The activities being undertaken through the watershed development projects inter alia include ridge area treatment, drainage line	पनधारा विकास परियोजना के जरिए अन्य कार्यों के साथ शुरू किए जा रहे

			treatment, soil and moisture conservation, rain water harvesting, nursery raising, afforestation, horticulture, pasture development, livelihoods for asset less persons, etc.	कार्यकलापों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकास लाइन उपचार, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधशाला निर्माण, वृक्षारोपण, बागवानी, चारागाह विकास और परिसंपत्त्िा विहीन व्यक्तियों आदि के लिए आजीविका स्रोत शामिल हैं।
80.	Preservation unit	संरक्षण इकाई	Under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) scheme, assistance for development of Post-Harvest Management (PHM) for establishment of cold storages, staging cold room, pack house, pre-cooling units, controlled atmosphere (CA) storage, reefer vans, primary/mobile processing units, integrated pack house, preservation unit (low cost), ripening chambers, onion storage at farm level etc. is provided for safeguarding agriculture produce.	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत, शीत भंडारण, स्तरीय शीत कक्ष, पैक हाउस, पूर्व-शीत इकाई, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रेफर वैन, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाइयाँ, समेकित पैक हाउस, संरक्षण इकाई (कम लागत), पकाई कक्ष, फार्म स्तर पर प्याज भंडारण आदि की स्थापना के लिए फसलोपरांत- प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता दी जाती है।
81.	Primary/mobile processing unit	प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाइयाँ	Under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) scheme, assistance is provided for primary/mobile processing units.	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता दी जाती है।
82.	Cultivator	खेतिहर किसान	Various schemes run by the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare aim at benefitting the cultivators irrespective	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित विविध स्कीमों का

			of the ownership status	लक्ष्य मालिकाना हक पर ध्यान दिए बगैर खेतिहर किसानों को लाभ पहुंचाना है।
83.	Agro-food product	कृषि-खाद्य उत्पाद	Ministry of Food Processing Industries is implementing Scheme for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) for promotion of processing/preservation of agro-food products including Mushroom processing units.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मशरूम प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों सहित कृषि-खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता तैयार करने/विस्तार हेतु स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।
84.	Sorting	छंटाई	The Central Government is providing free software and assistance for related hardware including quality assaying equipments and creation of infrastructure like cleaning, grading, sorting, packaging and compost unit etc.	केंद्र सरकार गुणवत्ता परख उपकरणों और अवसंरचनाओं जैसे सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और खाद इकाई आदि का निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर और सहायता प्रदान कर रही है।
85.	Long Range Forecast	दूरगामी पूर्वानुमान	As per second India Metrological Department (IMD) Long Range Forecast.	भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के दूसरे दूरगामी पूर्वानुमान के अनुसार है।
86.	Transplantations	रोपाई	In case of delayed sowing/transplantations DAC&FW take necessary steps.	देरी से बुवाई/रोपाई के मामले में डीएसीएंडएफडब्लयू आवश्यक कदम उठाता है।
87.	Drought Manual	सूखा नियमावली	As per the Manual for Drought Management, 2016 (Drought Manual), the State Government is required to declare drought through a notification for Kharif, not later than 31st October and for Rabi, not later than 31st March.	सूखा प्रबंधन के लिए नियमावली 2016 (सूखा नियमावली) के अनुसार, राज्य सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से खरीफ के लिए 31 अक्टूबर से पहले और

				रबी के लिए 31 मार्च से पहले सूखा घोषित करना अपेक्षित होता है।
88.	Input supplier	आदान आपूर्तिकर्ता	Details of farmers involved in Organic farming, input suppliers, certification agencies (PGS) and marketing agencies are available for smooth implementation from production to marketing.	उत्पादन से विपणन तक सुचारू कार्यान्वयन के लिए जैविक कृषि, आदान आपूर्तिकर्ताओं में शामिल किसानों तथा प्रमाणन एजेंसियां (पीजीएस) तथा विपणन एजेंसियों का विवरण उपलब्ध है।
89.	Organic fairs	जैविक मेले	Providing incentives for infrastructure creation, storage, grading, packaging, branding, publicity, transportation, value addition, development of integrated value chain and organic fairs.	अवसंरचना सृजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रचार, ढुलाई, मूल्यवर्धन, समेकित मूल्य श्रृंखला के विकास एवं जैविक मेलों के आयोजना के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
90.	Marketing platform	विपणन प्लेटफार्म	Government has launched a www.jaivikkheti.in portal acting both as a knowledge as well as marketing platform.	सरकार ने www.jaivikkheti.in पोर्टल शुरू किया है जो ज्ञान देने के साथ-साथ विपणन प्लेटफार्म दोनों के रूप में कार्य करता है।
91.	livestock	पशुधन	National Livestock Mission to increase productivity and genetic improvement of livestock.	पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और आनुवंशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।
92.	Multi dimensional inland and marine	बहु आयामी अंतर्देशीय एवं समुद्री	Foreseeing high potential in fisheries sector, a Blue Revolution with multi dimensional activities mainly focusing on fisheries production, both inland and marine is being implemented.	मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
93.	Genetic	आनुवंशिक	National Livestock Mission to increase	पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और

	improvement	सुधार	productivity and genetic improvement of livestock.	आनुवंशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।
94.	Pollination	परागण	Bee keeping has been promoted under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to increase the productivity of crops through pollination and increase the honey production as an additional source of income of farmers.	परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
95.	Bovines	गोवंशीय	Rashtriya Gokul Mission to enhance milk production and productivity of bovines and to make milk production more remunerative to the farmers.	गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।
96.	Back ended capital subsidy	पार्श्वांत पूंजी राजसहायता	AMI scheme is a back ended capital subsidy scheme.	एएमआई स्कीम एक पार्श्वांत पूंजी राजसहायता स्कीम है।
97.	Resource use efficiency	संसाधन उपयोग दक्षता	It is also the endeavour of the Government to increase productivity and resource use efficiency so as to make agriculture sustainable.	सरकार का यह भी प्रयास है कि कृषि को सतत आधार पर उपयोगी बनाने के लिए उत्पादकता और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाई जाए।
98.	Hybrid	संकर	In case of hybrids the higher yield is because of hybrid vigour not because of specific application of fertilizer.	संकर बीजों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संकर बीज के अधिक गुणवत्तायुक्त होने के कारण अधिक उपज होती है न कि उर्वरक के विशिष्ट अनुप्रयोग के कारण होती है।

99.	Electronic online trading platform	इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाईन व्यापार मंच	Launching of e-National Agriculture Market initiative to provide farmers an electronic online trading platform.	किसानों को इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाईन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी पहल शुरू की गई है।
100.	Joint liability groups	संयुक्त देयता समूह	There is provision in Kisan Credit Cards (KCC) scheme to provide loans to the tenant farmers through joint liability groups.	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में संयुक्त देयता समूहों के जरिए काश्तकारों को ऋण प्रदान करने का प्रावधान भी है।